

अमृत बनस्पति कंपनी व अन्य

बनाम

पंजाब राज्य व अन्य

मार्च 5, 1992

न्यायमूर्ति आर. एम सहाय और न्यायमूर्ति अस मोहन

प्रॉमिसरी एस्टोपेल/ वचन बंधन — प्रकृति सीमा और प्रयोज्यता
वचन— बंधन को कानून के विरुद्ध लागू नहीं किया जा सकता है।
सार्वजनिक नीति।

राज्य— प्रोत्साहन की नीति की घोषणा एवं व्यक्तियों को बिक्री कर
की वापसी सहित रियायत फोकल प्वाइंट में बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापित
करना— वनस्पति इकाई— प्राधिकरणों की स्थापना का आश्वासन रियायत
और प्रोत्साहन-बिक्री कर की वापसी का दावा— प्राधिकारियों की कार्रवाई को
न तो अनाधिकृत माना गया और न ही उससे परे। उनके अधिकार का
दायरा— धारणा के विरुद्ध रोक थी। सरकार-लेकिन बिक्री कर वापसी की
योजना इसके विपरीत है। सार्वजनिक नीति के लिए और अनुबंध की धारा
23 के तहत शून्य और कानून में लागू करने योग्य नहीं।

भारत का संविधान, 1950: अनुच्छेद 265.

कर लगाना — शक्ति की प्रकृति— कर लगाना संप्रभु शक्ति है .

कर लगाना -कर की वापसी-अनुमेयता और वैधता— कर वापस करने के लिए कोई भी कानून तब तक नहीं बनाया जा सकता जब तक कि कर लगा न दिया जाए कानून के विपरीत है— कर वापसी का वादा या समझौता एक है। संविधान पर धोखाधड़ी — कर से छूट और कर की वापसी — इनके बीच अंतर — छूट न तो अवैध है और न ही सार्वजनिक नीति के विरुद्ध — कर की वापसी, जब तक कि इसके विपरीत न लगाया गया हो कानून के अनुसार, अमान्य और अधिकारातीत होगा।

पंजाब सरकार ने दिसंबर में एक ब्रोशर जारी किया था, 1966 में अपनी 'नई नीति' की घोषणा करते हुए प्रोत्साहनों की घोषणा की और रियायत, उनमें से एक बिक्री-कर का रिफंड है उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध होगा जो सेट करने के इच्छुक थे फोकल प्वाइंट में चुनिंदा बड़े पैमाने के उद्योग। अपीलकर्ता की रियायतों और प्रोत्साहनों से आकर्षित मैनेजर ने जून 1968 में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पंजाब में वनस्पति स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की यदि इकाई को रियायत उपलब्ध करायी गयी तोह। पत्र दिनांक 2 जुलाई, 1968 के द्वारा उद्योग निदेशक द्वारा अपीलकर्ता को यह आश्वासन दिया कि रियायत दी जाएगी।

इसके बाद पत्र-व्यवहार का आदान-प्रदान हुआ। अपीलकर्ता के प्रतिनिधि व सरकारी अधिकारियों के बीच विभिन्न बैठकें हुई . पत्र दिनांक

२५ अक्टूबर, 1968 के द्वारा अपीलकर्ता ने रियायत की पुष्टि के लिए अनुरोध किया. 16 जून, 1969 के एक पत्र द्वारा यह पुष्टि की गई कि राज्य सरकार रियायत देने पर सहमत हो गई है। इस आश्वासन पर अपीलकर्ता ने जमीन खरीदी, जिसे एक अधिसूचना द्वारा जारी किया गया इस इकाई की स्थापना में पर्याप्त राशि का प्रयोग किया गया ।

इसके बाद, अपीलकर्ता ने बिक्री कर की वापसी का दावा किया जो की राज्य सरकार द्वारा तैयार उत्पाद पर लगाया जाता है । प्रत्यर्थी द्वारा धन वापस करने में विफल होने पर , अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की।

उच्च न्यायालय के एकल पीठ ने याचिका स्वीकार कर ली और सरकार को अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करने का वचन बंधन के सिद्धांत के आधार पर निर्देशित कर दिया।

अपील करने पर एकल पीठ के आदेश को डिवीजन पीठ द्वारा रद्द कर दिया गया डिवीजन पीठ ने कहा कि (i) सरकार द्वारा रियायत देने का निर्णय जून, 1969 में आया लेकिन उससे पहले यानी मई, 1969 में नीति में बदलाव आया था; (ii) कैबिनेट उप-समिति के निर्णय के मद्देनजर 1966 में ब्रोशर में ही बिक्री कर का कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा और परिणामस्वरूप की कार्रवाई सरकारी अधिकारी किसी भी अधिकार का सृजन अपने पक्ष में नहीं कर सकेगा अपीलकर्ता; और (iii) बिक्री के रूप में

भुगतान की गई राशि की वापसी अपीलकर्ता द्वारा कर की वापसी भारत के संविधान के अनुच्छेद 265 व 266 के विपरीत होगा।

अपील में राज्य की ओर से दलील दी गई थी कि (i) किसी भी आश्वासन के अभाव में राज्य की ओर से सक्षम प्राधिकारी वचन यदि कोई भी किसी भी इक्विटी को जन्म देने में असमर्थ था; और (ii) सरकार की नीति की घोषणा ब्रोशर में की गई है 25 अक्टूबर 1968 को भेजा गया अपीलकर्ता का केवल एक प्रस्ताव था जिसके अंतर्गत सरकार के विचार जिसने एक और जवाबी पेशकश की जिसे 16 जून को अपीलकर्ता ने स्वीकार कर लिया इसके बाद पंजीकरण और सरकार के लिए आवेदन किया ने फैक्ट्री को फोकल घोषित करते हुए अधिसूचना जारी कर दी।

इस न्यायालय ने अपील को खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित: 1. डिवीजन बेंच का निष्कर्ष तथ्यात्मक और कानूनी रूप से गलत माना गया। इसमें यह उचित नहीं था कि सरकारी अधिकारियों ने वादा अपने क्षेत्राधिकार से अधिक किया है।

वसंत कुमार राधाकिसन वोरा बनाम न्यासी मंडल बंबई बंदरगाह और अन्य, [1991] 1 एससीसी 761, को अनुपयुक्त माना गया।

2. सरकार अपने अधिकारियों आदि के माध्यम से कार्य करती है। लंबे समय से वे सरकार के अनुसरण में ईमानदारी से काम कर रहे हैं। सरकार को इस नीति से इनकार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

नागरिक के पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि क्या किया जा रहा है। सरकार अपने वादे से नहीं मुक्त सकती। इसकी फाइल में ऐसे दस्तावेज पड़े हैं जिनका न तो पता था और न ही घोषणा की, न ही उस पर कार्रवाई की गई क्योंकि यह अन्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण होगा, इसलिए यह अवैध है। यदि यह पाया जाता है कि प्रतिनिधित्व संबंधित अधिकारी द्वारा किया गया ऐसा था कि कोई भी उचित हो, व्यक्ति को विश्वास होगा कि यह की ओर से बनाया गया है, सरकार जब तक ऐसा प्रतिनिधित्व स्थापित न हो जाए अधिकार के दायरे से बाहर होने पर इसे बाध्यकारी माना जाना चाहिए।

2.1 मौजूदा मामले में रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है अधिकारी न केवल अपीलकर्ता को आश्वासन दे रहे थे लेकिन हर संभव प्रयास कर रहे थे की सरकार की नीति के अनुरूप यूनिट स्थापित हो जाये। ऐसा के जिम्मेदार एवं वरिष्ठ अधिकारियों का अथक प्रयास राज्य न तो अनधिकृत था और न ही उनके दायरे से बाहर था।

3. इस निष्कर्ष में कोई योग्यता नहीं है कि उस समय तक सरकार लिखित रूप में रियायत देने पर सहमत हुई नीति में बदलाव आ गया था। एस्टोपेल सरकार के पत्र दिनांक 16 जून 1969 के विरुद्ध नहीं उठा बल्कि दिसंबर, 1968 में किये वादा के विरुद्ध उठा था। इसके द्वारा अधिकारियों ने लिखित और मौखिक दोनों रूप से अपीलकर्ता को विश्वास दिलाया की है

इसका उद्देश्य एक समझौता बनाना था की भुगतान किया गया बिक्री कर वापस कर दिया जाएगा जिसके परिणामस्वरूप बहुत पहले ही जमीन, मशीनरी और अन्य हिस्से खरीदे गए थे। नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ लेकिन सरकार ने जारी कर दिया की फैक्ट्री का स्थान फोकल पॉइंट होगा।

पुरनामी ऑयल मिल्स आदि बनाम केरल राज्य, [1987] 1 एस.सी.आर. 654. एवं सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर वी. धरणेंद्र ट्रेडिंग कंपनी, [1988] 3 एस.सी.आर. 946, संदर्भ लिया गया।

4. पूरा तर्क प्रस्ताव और प्रतिवाद पर आधारित है। प्रस्तुत करने में कोई योग्यता नहीं है। अपीलकर्ता के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद सरकार 16 जून, 1969 को एक जवाबी प्रस्ताव दिया गया। यह केवल अपीलकर्ता द्वारा दी गई सूचना थी, इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया गया क्योंकि यह आश्वासन दिया गया है कि घोषित रियायतें इसे उपलब्ध होंगी।

5. प्रॉमिसरी एस्टोपेल के सिद्धांत का विस्तार है समता, जिसका मूल उद्देश्य न्याय को बढ़ावा देना है निष्पक्षता पर आधारित और किसी भी अन्याय से मुक्ति का वादा, वादा करने वाले के अपने वादे से मुकरने के कारण ऐसा होता है। यदि वादा किया गया है तो उसे अदालत में लागू करने में असमर्थ है, जो कार्रवाई का कारण या समझौते को प्रस्तुत करता है, निहितार्थ की अभिव्यक्ति बाध्यकारी अनुबंध को जन्म देती है, वैधानिक

रूप से निषिद्ध है या , सार्वजनिक नीति के विरुद्ध है।

भारत संघ बनाम इंडो अफगान एजेंसियां, [1968] 2 एस.सी.आर. 366; भारत संघ बनाम गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, [1985] 4 एससीसी 370 और दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स लिमिटेड बनाम।भारत संघ, [1988] 1. एस.सी.आर.383, संदर्भित।

6. कराधान राज्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली संप्रभु शक्ति है राजस्व का एहसास करने के लिए इसे इसका निर्वहन करने में सक्षम बनाना इसका दायित्व है। यहां तक कि एक विधायिका तो बिल्कुल भी कोई कानून नहीं बना सकती या कोई आदेश जारी नहीं कर सकती या वापसी के लिए सहमत नहीं हो सकती। अपनी संप्रभुता का प्रयोग करते हुए लोगों से इसके द्वारा वसूला गया कर शक्तियां, सिवाय इसके कि जब लेवी या वसूली इसके विपरीत हो कानून वैध रूप से अधिनियमित हुआ। कर वापसी का वादा या समझौता जो अधिनियम के तहत देय है और उसके अनुसार वसूल किया गया है, कानून संविधान के साथ धोखाधड़ी और आस्था का हनन होगा।

हैल्सबरीज लॉज ऑफ़ इंग्लैंड, खंड, 52; पैरा 20.04, उल्लेखनीय है।

7. औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए कर से छूट एवं कर वापसी के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। वे दो ही अलग हैं । छूट एक वर्ग को दी गई रियायत है जो की वैध और उचित कारण से सामान्य बोझ के व्यक्ति

पर लागू होती है । किसी अधिनियम या अधिसूचना या आदेश में ऐसा प्रावधान सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश न तो अवैध हैं और न ही जनता के खिलाफ हैं।

7.1 लेकिन कर की वापसी अधिक होने पर की जाती है. इसका भुगतान या इसकी वसूली अवैध रूप से या इसके विपरीत कानून के प्रावधान. वापसी का प्रावधान या समझौता कानून के अनुसार कर देय या वसूला नहीं जा सकता .टैक्स वापस करने के लिए कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। निर्माता को एक कानून के तहत एहसास हुआ। यह अमान्य होगा और अधिकारातीत. एक समझौता या यहां तक कि एक अधिसूचना या देय बिक्री कर की वापसी की अनुमति देने का आदेश दिया जाएगा।

7.2 पंजाब की न तो धारा 12 और न ही धारा 30 बिक्री कर अधिनियम सरकार को बिक्री कर वापस करने का अधिकार देता है किसी निर्माता द्वारा अपने तैयार उत्पाद की बिक्री पर प्राप्त किया गया। यदि भुगतान किया गया कर राशि से अधिक है तो रिफंड की अनुमति दी जा सकती है ऐसे रिफंड के लिए कोई भी समझौता जनता के विपरीत है. अनुबंध अधिनियम की धारा 23 के तहत पॉलिसी अमान्य थी। कर लगाने की संवैधानिक आवश्यकताएँ किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि समाज के कल्याण के लिए सरकार द्वारा किया गया समझौता या वादा था। सार्वजनिक उद्देश्य का उल्लंघन इस प्रकार जनता का उल्लंघन है। ऑपरेशन से कोई कानूनी

संबंध उत्पन्न नहीं हो सकता था वचन-बंधन का, क्योंकि यह दोनों के विपरीत था। संविधान और कानून. राज्य के माध्यम से कर की वसूली इसे सीधे निजी व्यक्ति को भुगतान करने की व्यवस्था या परोक्ष रूप से संवैधानिक योजना के तहत अनुमति योग्य नहीं है। कानून इसकी अनुमति नहीं देता और न ही समानता इसका समर्थन कर सकती है। इस प्रकार बिक्री कर की वापसी की योजना अक्षम थी कानून की अदालत में लागू किया जा रहा है।

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील नं. 1979 का 2832,2833

सिविल रिट संख्या में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 25.1.1977 से। 1975 का 5653 और पत्र पेटेंट अपील संख्या। 1975 का 368

कपिल सिब्बल यू.के. अपीलकर्ताओं की ओर से प्रवीण कुमार और विवेक सिब्बल

डी.एस. मेहरा श्रीमती जयश्री आनंद, अरुण मेहरा, संजय बंसल और जी.के. उत्तरदाताओं के लिए बंसल

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति आर. एम. सहाय द्वारा दिया गया था। वचन विबंदन, इसकी सीमा और प्रयोज्यता, इसकी सीमा और प्रयोज्यता, इसके अलावा, एक महत्वपूर्ण मुद्दा, जो इस अपील में विचार के लिए उठता है, लेटर्स पेटेंट के तहत क्षेत्राधिकार का उपयोग करने वाले

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच के फैसले और आदेश के खिलाफ निर्देशित है और विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द करते हुए रिफंड का निर्देश दिया गया है। बिक्री कर और अंतर-राज्य बिक्री कर, तब होता है जब किसी राज्य की सरकार किसी निर्माता द्वारा प्राप्त बिक्री कर को वापस करने के लिए स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से सहमत हो सकती है।

विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पाए गए तथ्य, जो सरकार को प्रॉमिसरी एस्टोपेल के सिद्धांत पर अपीलकर्ता को बिक्री कर वापस करने की अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने के लिए निर्देशित करने के लिए पर्याप्त थे, सरकार द्वारा उन लोगों के लिए प्रोत्साहन के रूप में बिक्री कर वापस करने की नीति की घोषणा की गई थी जो फोकल प्वाइंट्स में बड़े पैमाने पर चुनिंदा उद्योग स्थापित करने के इच्छुक थे, अपीलार्थी का पत्र जिसमें नीति का विवरण मांगा गया था क्योंकि वह एक वनस्पति विनिर्माण इकाई स्थापित करने का इच्छुक था, उद्योग निदेशक से अनुकूल प्रतिक्रिया के बाद उनके बीच पत्रों का और बैठकों आदान-प्रदान का हुआ। अपीलार्थी के प्रतिनिधियों और उद्योग सचिव ने आश्वासन दिया कि अपीलार्थी को प्रोत्साहन उपलब्ध होगा जिस पर उसने भूमि, मशीनरी आदि खरीदी थी, सरकार द्वारा आधारशिला रखी जाएगी और न ही उस भूमि की घोषणा करने वाली अधिसूचना जारी की जाएगी, जिस पर इकाई स्थापित की गई थी। आदेश को अपील में दरकिनार कर दिया गया था और यह

अभिनिर्धारित किया गया था कि भले ही सभी सरकारी और सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा न्यायसंगत रोक के नियम का पालन किया जाना चाहिए, लेकिन इसका दायरा सीमित था और इसे इतना व्यापक रूप से विस्तारित नहीं किया जा सकता था कि सरकार को तब भी बाध्य किया जा सके जब उसके अधिकारी अपने अधिकार से अधिक या सरकार के हित के खिलाफ हो। पीठ ने अपीलकर्ता के खिलाफ लिखित आश्वासन मांगने वाले अपने पत्रों से निष्कर्ष निकाला जिसमें लिखित आश्वासन की मांग की गई थी कि यह रियायत उसे दी जाएगी जो जून, 1969 में भी आई थी, लेकिन इससे पहले नीति में मई, 1969 में पहले ही बदलाव हो चुका था। पीठको यह जानकर हैरानी हुई कि हालांकि कैबिनेट उप-समिति ने 1966 में बिक्री कर का कोई रिफंड नहीं देने का निर्णय लिया था, फिर भी सरकारी अधिकारियों ने इसके विपरीत काम करते हुए विवरणिका जारी की और अपीलकर्ता के साथ पूरी तरह से अनधिकृत तरीके से पत्र-व्यवहार किया, इसलिए उनकी कार्रवाई अपीलार्थी के पक्ष में कोई अधिकार पैदा नहीं कर सकी। इसने अपीलार्थी के दावे को भी नकार दिया, क्योंकि अपीलार्थी द्वारा बिक्री कर के रूप में भुगतान की गई राशि की वापसी, सरकार द्वारा न तो अपने लिए या जनता के लिए बल्कि एक निजी व्यक्ति के लिए राजस्व बढ़ाना होगा जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 265 और 266 के विपरीत होगा।

प्रॉमिसरी एस्टोपेल का कानून, जिसे भारत संघ बनाम इंडो अफगान एजेंसियों [1968] 2 एससीआर 366 में 'सबसे स्पष्ट व्याख्या' मिली,

मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स बनाम यूपी राज्य, [1972] 2 एससीआर 641 में प्रस्तुत कारण के रूप में स्पष्ट किया गया किसी नागरिक द्वारा सरकार के खिलाफ कार्रवाई, कानून की अदालत में लागू करने योग्य है ,अगर सरकार या उसके अधिकारियों ने अपने अधिकार के दौरान कोई वादा किया था जो कानूनी संबंध बनाता था या सक्षम था, और और इस पर किसी भी पूर्वाग्रह के बावजूद वादा किए गए व्यक्ति द्वारा उस पर कार्रवाई की गई थी। इसे भारत संघ बनाम गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, [1985] 4 एस. सी. सी. 370 में दोहराया गया था और इसे तब आगे बढ़ाया गया जब यह अभिनिर्धारित किया गया कि निर्धारिती द्वारा निर्मित सिगरेट पर कोई उत्पाद शुल्क देय नहीं था, जिसमें जालीदार फाइबरबोर्ड पात्रों की लागत शामिल थी, जब इसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा सिगरेट निर्माता संघ द्वारा प्रस्तुत किए जाने के जवाब में स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया था-और इस प्रतिनिधित्व को केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित और स्वीकार किया गया था कि जालीदार फाइबरबोर्ड पात्रों की कीमत उत्पाद शुल्क के मूल्यांकन के उद्देश्य से सिगरेट के मूल्य में शामिल नहीं होगी। दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ, [1988] 1 एससीआर 383 यह आयोजित किया गया था।

" अब बस इतना ही आवश्यक है कि एस्टोपल का दावा करने वाली पार्टी ने उसे दिए गए आश्वासन पर कार्रवाई की होगी। उसे दिए गए

प्रतिनिधित्व पर भरोसा किया होगा । इसका मतलब है पार्टी आश्वासन या प्रतिनिधित्व पर भरोसा करके स्थिति बदल दी है । इस सिद्धांत की एकमात्र अनिवार्य आवश्यकता, पार्टी द्वारा स्थिति में परिवर्तन है। रोक लगाने वाली पार्टी को किसी भी नुकसान, नुकसान या पूर्वाग्रह को साबित करना आवश्यक नहीं है"।

इसलिए, जिस बात की जांच करने की आवश्यकता है, वह यह है कि यदि सरकार या उसके अधिकारियों द्वारा अपीलार्थी से कोई वादा किया गया था कि बिक्री कर इसे वापस किया जाएगा और उस पर कार्य करने वाले अपीलार्थी ने अपनी स्थिति बदल दी है। इसके लिए कुछ तथ्यों का वर्णन करना आवश्यक है, हालांकि विद्वान एकल न्यायाधीश और खंड पीठ दोनों ने इसे विस्तार से विचार किया है। माना जाता है, पंजाब सरकार द्वारा दिसंबर 1966 में अपनी 'नई नीति' की घोषणा करते हुए एक विवरणिका जारी की गई थी जिसमें घोषणा की गई कि प्रोत्साहन और रियायत, जिनमें से एक बिक्री कर की वापसी है, उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध होगी जो केंद्र बिंदु में चुनिंदा बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापित करेंगे । क्या यह विवरणिका अधिकृत थी या नहीं और पक्षों के अधिकारों पर इसका कनूनी प्रभाव

बाद में विज्ञापित किया जाएगा। लेकिन यह निर्विवाद है कि इस पर कार्रवाई करते हुए अपीलार्थी के प्रतिनिधि ने राज्य के मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और पाया कि वह राज्य में वनस्पति

विनिर्माण इकाई को प्रोत्साहित करने में रुचि रखते हैं, इसलिए इसके प्रबंधक ने जून, 1968 में मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा जिसमें इकाई स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की गई बशर्ते कि इसे रियायतें उपलब्ध कराई जाएं जिसका जवाब उद्योग निदेशक ने 2 जुलाई, 1968 को अपीलार्थी को आश्वासन देते हुए दिया कि घोषित रियायत के रूप में उपलब्ध होगा और अपीलार्थी को आगे सूचित किया जाएगा कि सरकार ऐसी अतिरिक्त रियायत पर विचार करने के लिए तैयार है जिसकी अपीलार्थी को योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यकता हो सकती है। इसके बाद अपीलार्थी के प्रतिनिधि और सरकार के अधिकारियों के बीच पत्राचार और विभिन्न बैठकों का आदान-प्रदान हुआ। इसका परिणाम उद्योग सचिव द्वारा वित्त विभाग को 1.4.1969 पर प्रस्तुत किए गए नोट में दर्ज किया गया है, जिसमें उसके द्वारा किए गए कुछ प्रश्नों पर, जिसके प्रासंगिक भाग में लिखा है।

" चूंकि राजपुरा में सरकारी निवेश हुआ था, औद्योगिक भूखंडों के आवंटन के लिए नियुक्त उप-समिति इसे आवंटित करने के लिए बहुत चिंतित थी, लेकिन उसे उपयुक्त पक्ष प्राप्त करने में कठिनाई हो रही थी। अक्टूबर, 1968 में गाजियाबाद के अमृत बनस्पति कारखाने के श्री खेतान ने मुझसे और डी. आई. से पंजाब में प्रति दिन 100 टन क्षमता के अपने बनस्पति संयंत्र के स्थान के लिए संपर्क किया। ये लोग क्योंकि वे पहले से ही व्यवसाय में बहुत थे और चूंकि उनका बनस्पति घी पंजाब की बनस्पति का 20 से 25 प्रतिशत जरूरतों को पूरा कर रहा था, यह महसूस किया

गया कि अगर हम इन लोगों को पंजाब आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो इससे औद्योगिक विकास को बहुत बढ़ावा मिलेगा। ये लोग मुख्य रूप से पंजाबकी ओर आकर्षित हुए थे जहां कच्चे माल की उपलब्धता, यानी मूंगफली जो लगभग पर्याप्त मात्रा में हैं। परिणामस्वरूप उन्होंने ढंडरी कलां में एक भूखंड की मांग की। उस समय लुधियाना में वनस्पति संयंत्र स्थापित करने के लिए हमारे पास दो-तीन आवेदन थे और चूंकि हमारे राजपुरा एस्टेट की बहुत उपेक्षा की गई थी, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि हम इस पक्ष को राजपुरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए राजी करें क्योंकि उनके वहां आने से यह महसूस किया गया कि कई छोटी और सहायक इकाइयां भी मिलेंगी और हमारे भूखंड बेचे जाएंगे। वास्तव में श्री खेतान ने मेरे साथ अपनी चर्चा के दौरान उल्लेख किया कि उनकी परियोजना, जिसकी लागत लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से अन्य छोटी इकाइयों-टिन निर्माताओं-की स्थापना की आवश्यकता होगी जो उत्तर प्रदेश से आए और राजपुरा में बस गए। इन सभी को लेते हुए जिन कारकों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस मामले का उल्लेख श्री .. और उस स्तर पर एफ. एस. को भी अनौपचारिक रूप से किया और यह निर्णय लिया गया कि हम इस पार्टी को राजपुरा में स्थित करेंगे। दुर्भाग्य से, इस पक्ष द्वारा भूमि की मांग एक स्थान पर 15 से 20 एकड़ की थी और चूंकि हमारे भूखंड केवल डेढ़ एकड़ के आकार के थे, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि उन्हें हमारे फोकल पॉइंट के पास अपने भूखंड का पता लगाने की

अनुमति दी जा सकती है ताकि इसे राजपुरा में औद्योगिक संपदा के हमारे भविष्य के विस्तार में अंततः एकीकृत किया जा सके, जिसमें अभी तक जीवन का कोई संकेत नहीं दिखता है और परिणामस्वरूप यह महसूस किया गया कि इस पार्टी को लाने से संबद्ध प्रकृति के अधिक उद्योग यहां आएंगे ताकि इसे अंततः एकीकृत किया जा सके। 1969-70 के लिए योजना में एफ. डी. को पता है कि हमारे पास भूमि के आगे के अधिग्रहण के लिए बहुत कम धन है। इस बात को समझते हुए, हमने इस पक्ष को सुझाव दिया कि वे खुद भूमि खरीद लें क्योंकि हमें यकीन नहीं था कि हमारे पास राजपुरा में विशेष रूप से जब हमारे पहले के भूखंड नहीं बेचे गए थे और अधिक भूमि अधिग्रहण करने के लिए पर्याप्त धन होगा या नहीं। यह पार्टी आने के लिए उत्सुक थी क्योंकि यह नवंबर, 1969 से उत्पादन में आना चाहती थी। पार्टी ने भूमि का वह टुकड़ा खरीदा है जिसे नगर और ग्राम योजना विभाग की मंजूरी है, उसने भवनों आदि के निर्माण के लिए अपनी योजना भी प्रस्तुत की है।"

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी के समक्ष यह प्रतिनिधित्व था कि वह सरकार द्वारा घोषित रियायत और प्रोत्साहन का हकदार होगा, यदि यह केंद्र बिंदु में अपनी इकाई स्थापित करता है। क्या इस तरह के प्रतिनिधित्व के परिणामस्वरूप बाध्यकारी समझौता हुआ है, यह अलग मुद्दा है, लेकिन सरकारी नीति के अनुसरण में उद्योग सचिव और उद्योग निदेशक से आने वाले प्रतिनिधित्व को अनधिकृत या प्राधिकरण के दायरे से बाहर

नहीं माना जा सकता है। सरकार अपने अधिकारियों के माध्यम से कार्य करती है और इसलिए जब तक वे सरकारी नीति के अनुसरण में ईमानदारी से काम कर रहे हैं, सरकार को इसे अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि एक नागरिक के पास यह जानने का कोई साधन नहीं हो सकता है कि है कि जो किया जा रहा है वह सरकार की मौन स्वीकृति के साथ था। और यदि यह पाया जाता है कि संबंधित अधिकारी द्वारा किया गया प्रतिनिधित्व ऐसा था कि कोई भी उचित व्यक्ति यह मान लेगा कि यह सरकार की ओर से किया गया है, तो जब तक ऐसा प्रतिनिधित्व प्राधिकरण के दायरे से परे साबित नहीं हो जाता, तब तक इसे बाध्यकारी माना जाना चाहिए। यह एक और बात है कि भले ही यह बाध्यकारी हो, यह कानून के विपरीत हो सकता है और इसलिए अप्रवर्तनीय हो सकता है। मोतीलाल पदमपत चीनी मिल (उपरोक्त) में सरकार को चीनी मिल को बिक्री करपर छूट देने के लिए बाध्य ठहराया गया था। भले ही निर्माता ने सचिव द्वारा जारी एक बयान के आधार पर ,बिक्री कर से छूट देने के लिए प्रकाशित एक समाचार पर उद्योग निदेशक को पत्र लिखा था जिसका सबसे पहले निदेशक द्वारा अनुकूल जवाब दिया गया था।बाद में मुख्य सचिव द्वारा उद्योगों का समर्थन किया गया और निर्माता को सूचित किया गया कि सरकार अनुरोध पर विचार करने को तैयार है और आवश्यक प्रपत्र आदि सचिव उद्योग से प्राप्त किए जा सकते हैं । जैसा कि सचिव की टिप्पणी से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने सचिव के आश्वासन पर निजी तौर पर भूमि

खरीदी, जिसे सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना द्वारा केंद्र बिंदु में शामिल किया गया था। इस बात से इनकार नहीं किया गया है कि जनवरी, 1969 तक अपीलकर्ता ने 15 लाख की लागत से जमीन और विभिन्न अन्य सामग्री खरीदी थी और 35 लाख रुपये मूल्य के संयंत्र और मशीनरी की खरीद का ऑर्डर दिया था, जिसकी सूचना 11 जनवरी, 1969 को भेजे गए तार द्वारा दी गई थी। यहाँ तक कि फरवरी, 1969 में भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी से नियम बनाए गए थे, जिसमें नए और विस्तार करने वाले उद्योगों को बिक्री और खरीद कर की वापसी का प्रावधान था। यह सब इंगित करता है कि वादा सरकार की ओर से उसके अधिकारियों द्वारा सरकार द्वारा नीति की घोषणा के अनुसरण में और उसके अनुरूप किया गया था कि एक नई इकाई रियायत का हकदार होगी। व्यक्त और निहित दोनों आश्वासनों पर कार्रवाई करते हुए, अपीलार्थी ने इकाई की स्थापना में पर्याप्त राशि का निवेश किया, इस बीच, सरकार से लिखित मंजूरी देने का अनुरोध किया, जो भी आई। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो भी इससे कानून में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इक्विटी अपीलकर्ता के पक्ष में 16 जून, 1969 के पत्र से नहीं, बल्कि अधिकारियों द्वारा दिए गए आश्वासन पर अपनी स्थिति में बदलाव करके अपीलार्थी के पक्ष में उत्पन्न हुई थी। गॉडफ्रे फिलिप्स (ऊपर) में यह देखा गया था,

" अब भारत के प्रशासनिक कानून में प्रोमिसरी एस्टोपल का सिद्धांत अच्छी तरह से स्थापित है, यह एक सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है

अन्याय से बचने के लिए समानता द्वारा विकसित किया गया और, हालांकि इसे आम तौर पर प्रोमिसरी एस्टोपेल नाम दिया गया है, यह न तो संविदा के दायरे में है और न ही विबंधन के दायरे में है। इस सिद्धांत का आधार समानता का अंतर्विरोध है, जिसने हमेशा, अपने स्वरूप के अनुरूप, सख्त कानून की कठोरता को कम करने के लिए कदम उठाया है। "

सरकार द्वारा किए गए वादे के बुनियादी तत्व, अपीलकर्ता का यह विश्वास कि यह सच था और यदि उस पर कार्रवाई की जाती है, तो वह इसे बिक्री कर की वापसी का हकदार बनाता है और अंत में पर्याप्त राशि का निवेश करके अपनी स्थिति में बदलाव करके सरकार के खिलाफ प्रोमिसरी एस्टोपेल को लागू करने के लिए स्थापित किया गया ।

पंजाब राज्य की ओर से विद्वान वकील का जोरदार तर्क दिया गया, कि राज्य की ओर से किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी आश्वासन के अभाव में, यदि कोई वादा किसी भी इक्विटी को जन्म देने में असमर्थ था, तो यह दिखाने के लिए कोई सकारात्मक सामग्री के अभाव में स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि सरकार ने उद्योग सचिव या निदेशक द्वारा भेजे गए पत्र से या तो खुद को अलग कर लिया या उनके द्वारा कथित रूप से प्रतिनिधित्व या आश्वासन के विपरीत कार्य किया। दूसरी ओर, सचिव की टिप्पणियाँ, जो पहले निकाली गई थीं, स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती हैं कि अधिकारी न केवल अपीलकर्ता को आश्वासन दे रहे थे, बल्कि हर संभव

प्रयास कर रहे थे कि इकाई को सरकार की नीति के अनुरूप स्थापित किया जाए क्योंकि इससे औद्योगीकरण का और विकास होगा। राज्य के जिम्मेदार और वरिष्ठ अधिकारियों का ऐसा श्रमसाध्य प्रयास न तो अनाधिकृत था और न ही उनके अधिकार के दायरे से बाहर था। वास्तव में दिनांक 16 जनवरी, 1969 का पत्र और उस भूमि की घोषणा करने वाली अधिसूचना जहां अपीलकर्ता की इकाई को रियायत का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए केंद्र बिंदु में स्थापित किया गया था, केवल अनुवर्ती कार्रवाई थी जो ऐसे किसी भी निष्कर्ष को ध्वस्त कर देती है, जैसा कि विद्वान वकील द्वारा प्रचार किया गया था।

प्रस्ताव, प्रति-प्रस्ताव और पुनः प्रति-प्रस्ताव के एक अभिनव प्रस्तुतिकरण को आगे बढ़ाने का भी प्रयास किया गया। यह प्रस्तुत किया गया था कि विवरणिका में घोषित सरकार की नीति केवल एक प्रस्ताव थी । और 25 अक्टूबर, 1968 को भेजा गया अपीलार्थी का पत्र एक जवाबी प्रस्ताव था जो सरकार के विचाराधीन था जिसने 16 जून को एक और जवाबी प्रस्ताव दिया जिसे अपीलार्थी द्वारा स्वीकार कर लिया गया, जिसने बाद में पंजीकरण के लिए आवेदन किया और सरकार ने कारखाने को केंद्र बिंदु में घोषित करते हुए एक अधिसूचना जारी की। यहां केवल इतना कहा जा सकता है कि प्रस्तुतिकरण बिना किसी आधार के आगे बढ़ाया गया था, पूरी तरह से प्रस्ताव और जवाबी प्रस्ताव के कानून के बारे में तथ्यों और गलतफहमी के संबंध में है। 2 जुलाई 1968 के पत्र के अनुसार उद्योग

सचिव को दिनांक 25 अक्टूबर 1968 को पत्र लिखा गया था और अपीलकर्ता के प्रतिनिधि और उद्योग सचिव के बीच 16 अक्टूबर 1968 को चंडीगढ़ में हुए साक्षात्कार के संदर्भ में यह पत्र लिखा गया था, राजपुरा में एक कारखाना स्थापित करने के लिए , जो औद्योगिक संपदा की लेआउट योजना के दायरे में आने वाले क्षेत्र के भीतर विभाग द्वारा अनुमोदित एक स्थल है, इस आश्वासन के साथ कि भूखंड राजपुरा में केंद्र बिंदु में होगा और यदि आवश्यक हो तो इसे केंद्र बिंदु में शामिल करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। पत्र में उल्लेख किया गया है कि नीति के अनुसार अपीलार्थी को उपलब्ध रियायत पांच साल की अवधि के लिए अंतर-राज्य बिक्री कर सहित खरीद और बिक्री कर की वापसी होगी। पत्र के पैराग्राफ 6 में अपीलार्थी ने स्पष्टीकरण मांगा कि पांच वर्ष की अवधि की गणना पेशी की तिथि से की जायेगी।

पत्र के अनुच्छेद 7 में लिखा है,

"7. हम पंजाब राज्य में औद्योगिक विकास, कर्मचारी और श्रमिक कल्याण गतिविधियों, कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए आवास, उद्योग में उपयोग के लिए कृषि उत्पादों के अनुसंधान और विकास पर पैसा खर्च करना चाहेंगे। हमें ऐसा करने में सक्षम बनाने के लिए, यह अनुरोध किया जाता है कि अंतर-राज्य बिक्री कर सहित खरीद और बिक्री कर की राशि

वापस करने के बजाय, अंतर-राज्य बिक्री कर सहित खरीद और बिक्री कर की राशि के बराबर राशि वापस की जाए। हमारे द्वारा भुगतान किया जाएगा-उत्पादन की तारीख से शुरू होने वाली पांच साल की अवधि के लिए हर तिमाही हमें पूंजीगत अनुदान के रूप में भुगतान किया जाता है। यदि हमारा अनुरोध स्वीकार कर लिया जाता है, तो हम अपनी ओर से उपरोक्त सभी या किसी भी उद्देश्य के लिए इसका उपयोग करने का वचन देते हैं जैसा कि हम पंजाब राज्य में उचित समझते हैं। आप इस बात की सराहना करेंगे कि आखिरकार राज्य को लाभ होगा यदि रियायतों का उपयोग राज्य में उद्योग और अनुसंधान और कर्मचारियों और कल्याण की उन्नति के लिए किया जाता है और यह तभी संभव होगा जब हमारे अनुरोध पर अनुकूल विचार किया जाएगा।"

25 अक्टूबर, 1968 के पत्र में उल्लिखित रियायत की पुष्टि के लिए अनुरोध पत्र 11 जनवरी को भेजे गए टेलीग्राम और 3, 13 और 23 जनवरी, 1969 के पत्रों में दिनांक 25 अक्टूबर, 1968 को दोहराया गया था। 25 अक्टूबर, 1968 के पत्र को प्रति प्रस्ताव के रूप में पढ़ना बहुत अधिक होगा। अपीलकर्ता द्वारा यह सूचित किया गया था कि उसने इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया है क्योंकि उसे आश्वासन दिया गया है कि घोषित रियायतें उसे उपलब्ध होंगी। अनुरोध है कि रिफंड के लिए पांच साल की अवधि की गणना उत्पादन की तारीख से की जानी चाहिए, और पूंजीगत अनुदान हर त्रैमासिक बिक्री कर की राशि के बराबर किया जा

सकता है, जिसे सरकार द्वारा दिए गए प्रस्ताव का लाभ उठाने में गिरावट के रूप में पढ़ा जाना असंभव है। अनुरोध यह किया गया था कि यदि बिक्री कर या खरीद कर की वापसी के बजाय उन्हें पांच साल की अवधि के लिए हर तिमाही में इसके बराबर राशि का भुगतान किया जाए तो इससे वे राज्य के लाभ के लिए इसका उपयोग कर सकेंगे। यह वह अनुरोध था जिसे टेलीग्राम और पत्रों में दोहराया गया था लेकिन किसी भी समय अपीलकर्ता ने यह अनुरोध नहीं किया कि यदि पूंजी अनुदान का भुगतान नहीं किया गया है तो उसे बिक्री कर के संबंध में रियायत का लाभ नहीं मिलेगा। अनुरोध भुगतान की प्रकृति को बदलने का था न कि रिफंड का। इसे प्रतिप्रस्ताव भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अपीलकर्ता ने न केवल इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया, बल्कि सहमति के अनुसार जमीन भी खरीदी और मशीनरी आदि भी न ही इस दलील में कोई दम है कि अपीलकर्ता के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद सरकार ने 16 जून, 1969 को एक जवाबी प्रस्ताव दिया था, यह भूलकर कि पत्र जारी करना सरकार की कोई अलग कार्रवाई नहीं थी, बल्कि यह पहले की गई थी, इसके अलावा, 2 मई को विभिन्न अधिकारियों के बीच हुई एक बैठक में सचिव की पिछली टिप्पणियों से यह निष्कर्ष निकाला गया, जिसमें यह निर्णय लिया गया था। 'कि फोकल प्वाइंट पर लागू रियायत और प्रोत्साहन मेसर्स अमृत बनस्पति कंपनी लिमिटेड को घी उद्योग स्थापित करने के लिए उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली 12 एकड़ भूमि के संबंध में ही दी जाएगी।' 16

जून, 1969 का पत्र 2 मई, 1979 को लिए गए निर्णय का विश्वसनीय पुनरुत्पादन था, जिसमें अपीलकर्ता को सूचित किया गया था कि, 'राज्य सरकार औद्योगिक विकास के केंद्र बिंदु में एक इकाई को स्वीकार्य रियायतें और प्रोत्साहन देने के लिए सहमत हो गई है। वनस्पति घी के निर्माण के लिए आपके द्वारा इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव है। संपूर्ण तर्क एक प्रस्ताव और प्रति प्रस्ताव पर आधारित था, इस प्रकार, गलत धारणा थी।

सरकार को वचन-बंधन के सिद्धांत की कठोरता से बचने की अनुमति देने के लिए, उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा दो कारण दिए गए थे, एक यह कि ब्रोशर स्वयं अनधिकृत था और दूसरा यह कि जब सरकार का निर्णय आया तो नीति पहले ही आ चुकी थी। बदलाव आया. ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों में से कोई भी अच्छी तरह से स्थापित नहीं है। कैबिनेट उप-समिति का 15 दिसंबर, 1968 का निर्णय, जिसने इस निष्कर्ष का आधार बनाया कि ब्रोशर अनधिकृत था, उद्योग मंत्री और उद्योग सचिव की समिति के निर्णय के विवरण हैं, जिसे आज तक प्रकाशित नहीं किया गया। इसे डिवीजन बेंच के समक्ष पूरक हलफनामे के माध्यम से दायर किया गया था। इसके विपरीत, मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री ने इसके पांच दिन बाद यानी 20 दिसंबर, 1968 को चंडीगढ़ में उद्योगों के सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में घोषणा की कि फोकल में स्थापित नई इकाइयों को रियायत और प्रोत्साहन की पेशकश की जाएगी। दिसंबर, 1966 में सरकार द्वारा जारी की गई पुस्तिका में उन बिंदुओं का विवरण दिया गया था,

जिसमें अपीलकर्ता द्वारा दावा किए गए बिक्री कर की वापसी का प्रावधान था।

किसी राज्य के नागरिक के पास यह सुनिश्चित करने का कोई साधन नहीं हो सकता है कि मुख्यमंत्री और राज्य के उद्योग मंत्री की घोषणा कि पुस्तिका में दी गई छूट उपलब्ध होगी, सरकार की नहीं थी इससे पहले कैबिनेट उप समिति ने कुछ और नीति अपनाई थी फ़ैसला। सरकार को अपने वादे से पीछे हटने की इजाजत नहीं दी जा सकती इसकी फ़ाइल में पड़े कुछ दस्तावेज़ पेश करके जिनका न तो पता था, न तो इसकी घोषणा की गई और न ही इस पर कार्रवाई की गई क्योंकि यह अन्यायपूर्ण और अनुचित होगा, इसलिए यह अवैध है। तथ्यात्मक रूप से डिवीजन बेंच ने 15 दिसंबर, 1968 के में कार्यवृत्त बहुत कुछ पढ़ा है लेकिन इससे निपटना जरूरी नहीं है। यह कहना पर्याप्त होगा कि सरकार अपनी नीति को कैसे समझती थी और दूसरों को भी समझाना चाहती थी, इसका उल्लेख ब्रोशर में किया गया था। यहाँ तक कि उप-समिति के सदस्य सचिव ने भी इसे उसी प्रकार समझा जिस प्रकार यह पुस्तिका में छपा था। वित्त विभाग को सौंपे गए नोट में कहा गया,

"... रियायतें देने के पूरे मामले पर कैबिनेट स्तर पर चर्चा की गई और जब सरकार ने उद्योग को ऐसी आकर्षक रियायतें देने का निर्णय लिया तो इन सभी कारकों (अर्थात् बिक्री कर से छूट)* को ध्यान में रखा गया।

में चाहूंगा इस मामले को डी.एम. द्वारा भी देखा जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने मुझसे इस मामले के बारे में पूछताछ की थी। आई.एन. और एफ.एस.आर के रूप में अमृत बनस्पति लोग जानते हैं, वे पहले ही अपने भवन के निर्माण के लिए जा चुके हैं और उनकी योजना के अनुसार वे नवंबर 1969 उत्पाद में जाने का प्रस्ताव रखते हैं। वे चिंतित हैं कि सरकार उनकी इकाई को भी रियायत देने का शीघ्र निर्णय ले। चूंकि यह एक बड़ा उद्योग है इसलिए हमें तत्काल निर्णय लेना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से सहायक लाने की संभावना तलाशी जा सकती है जिससे यह सुनिश्चित हो सके। हमारी औद्योगिक संपदा यथाशीघ्र पूर्ण रूप से विकसित हो...।"

*[ब्रैकेट आपूर्ति]

जैसा कि पहले बताया गया है कि 16 जून, 1969 का पत्र 27 मई, 1969 की नोटिंग पर आधारित था, जो 22 मई, 1969 को आए निर्णय पर आधारित था। इस प्रकार, डिवीजन बेंच का निष्कर्ष तथ्यात्मक और कानूनी रूप से गलत था। यह मानना चित नहीं था कि सरकारी अधिकारियों ने अनाधिकृत रूप से और अपने अधिकार के दायरे से बाहर जाकर वादा किया था। वसंतकुमार राधाकिसन वोरा बनाम बॉम्बे पोर्ट के ट्रस्टी बोर्ड और अन्य पर निर्भरता, [1991] 1 एससीसी 761 एस्टेट मैनेजर के रूप में उपयुक्त नहीं था, जिसके कहने पर पट्टेदार ने पुनर्निर्माण के बाद किरायेदारी अनुदान के लिए राशि जमा करने के लिए अधिकृत किया था।

केवल किराया इसके अलावा पत्र में संकेत दिया गया कि यदि पट्टेदार शर्तों का अनुपालन करता है तो वह पट्टा देने के लिए बोर्ड को सिफारिश करेगा। और सिफारिश की गई लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया।

न ही उस समय की सरकार के निष्कर्ष में कोई दम है। इस बात पर सहमति जताते हुए कि नीति में रियायत देने के लिए लिखित रूप से परिवर्तन हुआ था, इसलिए अपीलकर्ता केवल नई नीति के तहत रियायत का हकदार था, एस्टोपेल सरकार के खिलाफ 16 जून, 1969 के पत्र से नहीं, बल्कि दिसंबर, 1968 में उन लोगों से किए गए वादे से खड़ा हुआ जो नई इकाई स्थापित करने के इच्छुक थे, इसके अधिकारियों द्वारा लिखित और मौखिक रूप से यह विश्वास करने के लिए आश्वासन दिया गया कि इसका उद्देश्य एक समझौता करना था कि भुगतान किया गया बिक्री कर वापस कर दिया जाएगा जिसके परिणामस्वरूप उसने न केवल नीति में कोई बदलाव होने से बहुत पहले भूमि, मशीनरी और अन्य पुर्जे खरीदे थे, बल्कि सरकार ने अधिसूचना जारी करने के साथ-साथ उस क्षेत्र को भी घोषित किया था जहां कारखाना स्थापित किया गया था। इसलिए दलों के अधिकार पुरानी नीति से नियंत्रित होते थे न कि नई नीति से। अपीलार्थी को कभी सूचित नहीं किया गया कि सरकार ने उच्च न्यायालय में जवाबी हलफनामा दाखिल करने से पहले किसी भी समय बिक्री कर की वापसी के संबंध में अपनी नीति में बदलाव किया है। यहां तक कि 16 जून, 1969 के पत्र में भी यह उल्लेख नहीं था कि नई नीति में दी गई रियायतें उपलब्ध

होंगी। पूर्णिमा ऑयल मिल्स आदि में v. केरल राज्य, [1987] 1 एस. सी. आर. 654 सरकार को अपने पहले के व्यापक वादे से पीछे हटने की अनुमति नहीं दी गई थी। बिक्री कर से छूट जिसके अनुसरण में उद्योग प्रतिभूति रोक के सिद्धांत पर स्थापित किए गए थे और एक वर्ष की कटौती छूट के बाद जारी अधिसूचना को उसके बाद स्थापित उद्योगों पर लागू करने के लिए आयोजित किया गया था। वाणिज्यिक करों के सहायक आयुक्त बनाम में भी यही निर्णय लिया गया है। धरणेंद्र ट्रेडिंग कंपनी [1988] 3 एस. सी. आर. 946।

लेकिन प्रॉमिसरी एस्टोपेल समानता के सिद्धांत के विस्तार पर होने के कारण, जिसका मूल उद्देश्य निष्पक्षता पर आधारित न्याय को बढ़ावा देना और वादा करने वाले के अपने वादे से पीछे हटने के कारण हुए किसी भी अन्याय के वादेदार को राहत देना है, कानून की अदालत में लागू होने में असमर्थ है यदि वह वादा जो कार्रवाई के कारण या समझौते को प्रस्तुत करता है, जो बाध्यकारी अनुबंध को जन्म देता है, वह वैधानिक रूप से निषिद्ध है या सार्वजनिक नीति के खिलाफ है। फिर रिफंड की प्रकृति क्या थी जिसका वादा सरकार ने किया था? क्या इस तरह का वादा कानून के विपरीत और सार्वजनिक नीति के खिलाफ था? क्या इसे अदालत में लागू किया जा सकता है? कराधान एक संप्रभु शक्ति है जिसका उपयोग राज्य द्वारा राजस्व प्राप्त करने के लिए किया जाता है ताकि वह अपने राजस्व का निर्वहन कर सके। दायित्व। ऐसा करने की शक्ति संविधान की सातवीं

अनुसूची की सूची I, II और III में प्रविष्टियों से प्राप्त होती है। बिक्री कर या खरीद कर सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 54 के तहत किसी राज्य द्वारा पारित अधिनियम से प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए लगाया जाता है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है जैसे कि यह है एक व्यापारी द्वारा एकत्र किया गया कानून आम तौर पर इसे पारित करने की अनुमति देता है और अंतिम बोझ उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाता है। लेकिन 'तथ्य यह है कि का बोझ। हो सकता है कि कोई कर उपभोक्ता को दे दिया गया हो, इससे कर की कानूनी प्रकृति में परिवर्तन नहीं होता है' (हेल्सबरी के इंग्लैंड के कानून, खंड 52, पैराग्राफ 20.04)। इसलिए एक विधायिका, यहां तक कि एक सरकार भी, कोई कानून नहीं बना सकती या कोई आदेश जारी नहीं कर सकती या अपनी संप्रभु शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोगों से वसूले गए कर को वापस करने के लिए सहमत नहीं हो सकती, सिवाय इसके कि जब लेवी या वसूली वैध रूप से अधिनियमित कानून के विपरीत हो। अधिनियम के तहत देय और कानून के अनुसार वसूले गए कर को वापस करने का वादा या समझौता संविधान और लोगों के विश्वास की शाखा के साथ धोखाधड़ी होगी। बिक्री कर जैसे करों का भुगतान एक गरीब व्यक्ति द्वारा भी अपनी बचत की परवाह किए बिना राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि और राज्य के विकास में भागीदारी की भावना से किया जाता है। राज्य में अपनी इकाई स्थापित करने के लिए प्रलोभन के रूप में भुगतानकर्ता को नहीं बल्कि एक निजी व्यक्ति, एक निर्माता को रिफंड के रूप में इसका

उपयोग लोगों के विश्वास का उल्लंघन होगा जो कानून के तहत धोखाधड़ी के बराबर होगा।

औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए कर से छूट को कर वापसी के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। वे दो अलग-अलग कानूनी और विशिष्ट अवधारणाएँ हैं। छूट किसी वर्ग या व्यक्ति को वैध और उचित कारण से सामान्य बोझ से दी जाने वाली रियायत है। उदाहरण के लिए, नए या विस्तारित उद्योगों को कर अवकाश या रियायत औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन देने के तरीकों में से एक माना जाता है। घोषित उद्देश्य उद्योग को बाजार में खड़े होने और प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाना है। बिक्री कर एक अप्रत्यक्ष कर है जो अंततः उपभोक्ता को दिया जाता है। यदि कोई उद्योग कर से मुक्त है तो अंतिम लाभार्थी उपभोक्ता है। उद्योग को दूसरों की तुलना में अपने उत्पादों को तुलनात्मक रूप से सस्ती दर पर बेचकर अपने शुरुआती दौर से उबरने की अनुमति है। इसलिए, निर्माता और उपभोक्ता दोनों को लाभ होता है, एक तो गैर-लेवी की रियायत से और दूसरा गैर-भुगतान की रियायत से। किसी अधिनियम या अधिसूचना या सरकार द्वारा जारी आदेशों में ऐसे प्रावधान न तो अवैध हैं और न ही सार्वजनिक नीति के विरुद्ध हैं।

लेकिन कर का रिफंड इसके अधिक भुगतान या अवैध रूप से या कानून के प्रावधानों के विपरीत इसकी वसूली के परिणामस्वरूप किया जाता

है। कानून के अनुसार देय या वसूले गए कर को वापस करने का प्रावधान या समझौता समझ में नहीं आता है। किसी कानून के तहत किसी निर्माता को वसूले गए कर को वापस करने के लिए कोई कानून नहीं बनाया जा सकता है। यह अमान्य और अधिकारातीत होगा। पंजाब बिक्री कर अधिनियम में बिक्री कर की वापसी और छूट देने का प्रावधान है जी क्रमशः धारा 12 और 30 में निर्दिष्ट परिस्थितियाँ। न तो उन्हें- सरकार को निर्माता द्वारा वसूले गए बिक्री कर को वापस करने का अधिकार दिया अपने तैयार उत्पाद की बिक्री पर। यदि कर का भुगतान किया गया हो तो रिफंड की अनुमति दी जा सकती है। देय राशि से अधिक में देय बिक्री कर की वापसी की अनुमति देने वाला कोई समझौता या अधिसूचना या आदेश भी कानून के विपरीत होगा। इसे स्पष्ट करने के लिए अपीलकर्ता ने अपने तैयार उत्पादों की बिक्री पर राज्य सरकार को भुगतान किए गए बिक्री कर की वापसी का दावा किया। लेकिन भुगतान किया गया कर अपीलकर्ता द्वारा खर्च की गई राशि नहीं है बल्कि बिक्री पर प्राप्त राशि है। इस मद में जो जमा किया जाता है वह कर है जो अन्यथा अधिनियम के प्रावधानों के तहत देय है। इसके या इसके समतुल्य का रिटर्न या रिफंड, चाहे जो भी हो, बिक्री कर का पुनर्भुगतान या रिफंड है। यह इसके संविधान विपरीत होगा। सार्वजनिक नीति के विपरीत होने के कारण ऐसे रिफंड के लिए कोई भी समझौता अनुबंध अधिनियम की धारा 23 के तहत शून्य था। कर लगाने की संवैधानिक आवश्यकताएं समाज के कल्याण के लिए हैं न कि

किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए, सरकार द्वारा किया गया समझौता या वादा सार्वजनिक उद्देश्य का उल्लंघन था और इस प्रकार सार्वजनिक नीति का उल्लंघन था। प्रॉमिसरी एस्टोपेल के संचालन से कोई कानूनी संबंध उत्पन्न नहीं हो सकता था क्योंकि यह संविधान और कानून दोनों के विपरीत था। निजी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भुगतान करने के लिए राज्य तंत्र के माध्यम से कर की वसूली संवैधानिक योजना के तहत अनुमति योग्य नहीं है। कानून इसकी अनुमति नहीं देता और न ही समानता इसका समर्थन कर सकती है। इस प्रकार बिक्री कर की वापसी की योजना अदालत में लागू होने में असमर्थ थी।

ऐसी संवैधानिक रूप से बाधित नीति की भ्रांति, सार्वजनिक हित का त्याग, जिसके परिणामस्वरूप अवैध निजी संवर्धन हुआ, लगभग रुपये के रिफंड के दावे से उजागर होता है। 2 करोड़, केवल तीन साल की अवधि के लिए, जब इकाई की स्थापना में कुल निवेश रु. 1.5 करोड़, राज्य की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए राजस्व बढ़ाने के लिए कर लगाने से निर्माता के लाभ मार्जिन में वृद्धि हुई और बिक्री कर अपीलकर्ता की आय में परिवर्तित हो गया। वैधानिक होते हुए भी कानून की ऐसी युक्ति कानूनी रूप से अप्रवर्तनीय है।

और परिणामस्वरूप यह अपील विफल हो जाती है और जुर्माने सहित खारिज कर दी जाती है।

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी **राकेश कटारा** (आर०जे०एस०) द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।